सफलता पाने के लिए पहले हमे विश्वास करना होगा की हम कर सकते है।
– अज्ञात

पर्सनल डेटा के इस्तेमाल

डेटा सुरक्षा की किसी मुकम्मल व्यवस्था के अभाव में एटीएम, डेबिट–क्रेडिट कार्ड और नेटबैंकिंग में फर्जीवाड़े की कई घटनाएं हो चुकी हैं। राजनीतिक दल चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए डेटा की फिराक में रहते हैं

राधा जोशी

विपक्ष के विरोध के बाद निजी डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को संसद की संयुक्त प्रवर समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया है। यह समिति बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि तब तक इस पर उठाई गई तमाम आपत्तियों के समाधान ढूंढ लिए जाएंगे और बिल को सर्वस्वीकार्य रूप दिया जा सकेगा। सरकार का तर्क है कि उसने देश में व्यापक विचार–विमर्श के बाद ही इसे तैयार किया है, जबकि विपक्ष और तमाम कानूनी विशेषज्ञों के अलावा कई संगठनों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। इस विधेयक के तहत पर्सनल डेटा के इस्तेमाल से पहले उपभोक्ताओं की मंजूरी जरूरी लेनी होगी, जबकि बायोमेट्रिक डेटा के लिए सरकार की मंजूरी आवश्ध्यक होगी। बच्चों के लिए इस मामले में सख्ध्त कानून होगा। सभी कंपनियों को अपने डेटा की तमाम जानकारियां सरकार के साथ शेयर करनी होंगी।

विधेयक में डेटा के स्थानीय भंडारण पर बल दिया गया है। भारतीयों का संवेदनशील डेटा भारत में ही स्टोर करना होगा और कुछ सीमित डेटा ही विदेश में स्टोर किया जा सकेगा। विधेयक में सरकार को फेसबुक और गूगल समेत तमाम विदेशी कंपनियों से गोपनीय निजी डेटा और गैर–निजी डेटा के बारे में पूछने का अधिकार दिया गया है। निजी डेटा की चोरी करने वाली कंपनियों पर सख्ती बढ़ाने की बात कही गई है। इसमें सरकारी एजेंसियों को क्रेडिट स्कोर, कर्ज वसूली और सुरक्षा से जुड़े मामलों में डेटा मालिक की सहमति के बिना भी उसकी डेटा प्रॉसेसिंग करने की छूट दिए जाने का प्रावधान है। सरकार को अधिकार होगा कि वह किसी भी सरकारी एजेंसी को प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के दायरे से छूट दे सके। इंटरनेट आने के बाद से निजी सूचनाओं की सुरक्षा का सवाल पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। इस तकनीक ने जहां हमारे रोजमर्रा जीवन में सहूलियतें पैदा की हैं, वहीं हमारी गोपनीयता में सेंध भी लगाई है। दरअसल इंटरनेट से जुड़ने का मतलब ही है कि हमें अपनी निजी सूचनाएं साझा करनी पड़ेंगी।

डेटा सुरक्षा की किसी मुकम्मल व्यवस्था के अभाव में एटीएम, डेबिट–क्रेडिट कार्ड और नेटबैंकिंग में फर्जीवाड़े की कई घटनाएं हो चुकी हैं। राजनीतिक दल चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए डेटा की फिराक में रहते हैं और सरकारें भी नीतियां बनाने वक्त डेटा को लेकर उत्सुक रहती हैं। इसलिए डेटा संरक्षण को कानूनी जामा पहनाने की जरूरत महसूस की जा रही है लेकिन इसमें चुनौती संतुलन बनाने की है।

गोपनीयता को लेकर समझौता तभी किया जा सकता है जब कोई निजी सूचनाओं का दुरुपयोग न कर सके। इसके लिए एक लक्ष्मणरेखा तय करने की बात है। कई देशों ने इसके लिए कानून बनाए हैं। हमें भी एक सख्त कानून की जरूरत है लेकिन इसकी आड़ में सरकार या किसी निजी एजेंसी को आंकड़ों पर अनियंत्रित अधिकार नहीं सौंपा जा सकता। देखें, अंतिम तौर पर यह बिल किस रूप में सामने आता है।

एकाकीपन

धर्म-दर्शन

मनमोहन। एक व्यक्ति अपनी जिन्दगी में कई सारे नुक्कड़ों से होकर गुजरता है... कई सारे संघर्षों और जद्दोजहद से लड़ता हुआ, अडिग अपने कर्म करता जाता है... लेकिन जब वो जिन्दगी के आखिरी नुक्कड़ की और जाने वाली सड़क पर होता है तो उसके पग भी हलके–हलके कांपते जरूर हैं... और जब वो देखता है कि उसके भाई ,बहन ,दोस्त ,और आस पास के सभी लोग उनके घर परिवार में व्यस्त है और उसके लिए किसीके पास वक्त ही नहीं है तब उस व्यक्ति को अपनेपन ,प्यार, और संबल की कीमत पता चलती है ! जो व्यक्ति स्वयं कभी ये कहता था की उसे किसीकी जरुरत नहीं है वो अकेला ही ठीक है और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियेगा ऐसे व्यक्ति को उम्र के उस पड़ाव पर जीवनसाथी का मोल क्या होता है तब पता चलता है।

संपादकीय

कांग्रेस में खलबली

लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में खलबली है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस विश्वसनीयता के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। उसके शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और उसकी जमीन खिसकती नजर आई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साबित किया कि पार्टी में कोई बड़ा अंदरूनी संकट है, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। आज के दौर में चुनाव लड़ने के लिए जिस कुशल प्रबंधन और प्रफेशनलिज्म की जरूरत है उसका कांग्रेस में अभाव दिखता है।

पिछले कुछ वर्षों में शायद ही कभी पार्टी ने व्यापक सदस्यता अभियान चलाया हो या कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए कोई कार्यशाला या शिविर आयोजित किए हों या उन्हें एकजुट करने के लिए किसी भी तरह की पहल की हो। आलाकमान ने नीचे तक अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। पहले पार्टी में कई ऐसे जमीनी नेता हुआ करते थे, जिनकी क्षेत्र या राज्य से ऊपर पहचान हुआ करती थी। उनकी बातों का एक असर हुआ करता था और वे अपने दम पर अपनी पार्टी को वोट दिलाया करते थे। पर अब ऐसे नेताओं का अकाल हो गया है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूरी तरह गांधी परिवार पर आश्रित हो गए हैं। इस चुनाव में ही कई सीनियर नेताओं ने अपने क्षेत्र से भी दूरी बनाए रखी। दरअसल, सोनिया गांधी के कमान संभालने के बाद पार्टी का चरित्र बहुत बदला है। इस पर शहरी संभ्रांत वर्ग का वर्चस्व हो गया है जो इसे एक गैर सरकारी संगठन की तरह चला रहा है। वह सिद्धांतों में जीने वाला एक तबका है, जिसे अंदाजा ही नहीं कि देश का सामाजिक यथार्थ कितना बदल चुका है।

...जैसे वार्ता से फिलहाल सीमा पर तनाव कम हो सकता है और सरहद पर रहने वाले दोनों तरफ के लोगों का रोजमर्रा का जीवन सामान्य हो सकता है।

भारत-पाक रिश्तों में सुधार

मोहन भट्ट

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोकसभा चुनाव में दूसरी बार भारी जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और उम्मीद जताई कि भारत–पाक संवाद की प्रक्रिया जल्द ही दोबारा शुरू होगी। इमरान ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर भारत–पाक रिश्तों में सुधार संभव है। अब देखना है कि नई सरकार का इस मामले में क्या रुख होता है। दोनों मुल्कों के बीच बातचीत वक्त की जरूरत है, लेकिन इस मामले में कुछ चीजें शुरू में ही साफ हो जानी चाहिए, ताकि पुरानी गलतियों से बचा जा सके। दरअसल भारत–पाक संबंधों में काफी समय से एक या दूसरी तरह का अतिरेक देखा जा रहा है। जब भी रिश्ते सामान्य होने शुरू होते हैं, दोनों तरफ कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं देखने को मिलती हैं। व्यापारिक, सांस्कृतिक, ऐकडेमिक, फिल्मी, हर तरह का आदान–प्रदान शुरू हो जाता है। ट्रैक–टू डिप्लोमेसी मुख्यधारा के राजनय पर हावी हो जाती है।

राजनेता भी अपनापन दिखाने के नए–नए तरीके ढूंढने लगते हैं। लगता है, एक झटके में सारी दीवारें गिर जाएंगी और रातोंरात एक नया इतिहास बन जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया का ऐंटी–क्लाइमेक्स कभी पाकिस्तानी फौज की किसी खुली या गुप्त हरकत या फिर एक भीषण आतंकवादी घटना के रूप में सामने आता है और एक ही झटके में सारी कोशिशों पर पानी फिर जाता है। देखते–देखते दोनों देश एक–दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। याद करें तो जनरल जिया उल हक के दौर में– जब दोनों देशों के बीच न बहुत गर्मजोशी थी न बहुत तनाव– हमारा रिश्ता ज्यादा संतुलित था। हालात बिगड़ने पर बातचीत से मामला संभल जाता था, क्योंकि दोनों की एक–दूसरे से अपेक्षाएं बहुत कम थीं।

आज फिर हमें अपने रिश्तों को व्यावहारिक धरातल पर ही देखना चाहिए। बातचीत शुरू करें, लेकिन यह आशा छोड़कर कि इससे आतंकवाद की समस्या हल हो जाएगी या कश्मीर की गुत्थी सुलझ जाएगी। छोटे लक्ष्य रखे जाएं। जैसे वार्ता से फिलहाल सीमा पर तनाव कम हो सकता है और सरहद पर रहने वाले दोनों तरफ के लोगों का रोजमर्रा का जीवन सामान्य हो सकता है। फिर स्थानीय स्तर पर थोड़ा–बहुत कारोबार शुरू हो जाए तो माहौल सुधारने के लिए यह भी कम नहीं है।

सहोदर भाई का आदर्श अगर हमसे नहीं सध पा रहा तो शांतिपूर्ण पड़ोसी की तरह रहने की कोशिश क्यों न करें? चीन के साथ हम दशकों से ऐसे ही रहते आ रहे हैं। उसके साथ सीमा विवाद आज भी 1962 के युद्ध वाले मुकाम पर ही टिका है। लेकिन हमने इस झगड़े को पिटारे में बंद करके आपसी कारोबार को बढ़ावा दिया। नतीजा यह कि चीन आज हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। चीनी नेता तंग श्याओफिंग ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कहा था कि टकरावों का समाधान हमें अगली पीढ़ियों पर छोड़ देना चाहिए। यह कहानी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भी क्यों नहीं दोहराई जा सकती?

सूडोकु नवताल-5192

✱✱✱✱✱ मध्यम

6	9			7	4		8	
	8	5	6	2			4	9
7						6		3
	3	9	5				1	
1				8				5
	6				2	9	3	
4		7						2
8	2			5	9	1	7	
	1		2	3			5	8

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5191 का हल

6	5	3	9	1	7	2	8	4
9	1	8	2	6	4	3	7	5
7	4	2	5	3	8	1	9	6
3	7	1	6	9	2	4	5	8
8	6	9	1	4	5	7	2	3
5	2	4	8	7	3	9	6	1
2	9	5	4	8	1	6	3	7
4	3	6	7	5	9	8	1	2
1	8	7	3	2	6	5	4	9

अपना ब्लॉग
केंद्र में अलग, राज्य में अलग

नरेंद्र नाथ। 2014 के बाद से ही बीजेपी क्षेत्रीय दलों के लिए भी खतरे की घंटी बन रही है। उससे पहले के सालों में देश में गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों ने अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाया था जिसकी वजह से सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा था। लेकिन 2017 में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर ऐतिहासिक जीत हासिल करके बीजेपी ने साबित कर दिया था कि अब वह क्षेत्रीय दलों के दुर्ग को तोड़ने के लिए तैयार दिख रही है। हालांकि अभी भी पूरे देश में तमाम दलों के विधायकों की संख्या देखें तो गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी के एमएलए की संख्या इन दोनों ही दलों से आगे है। लेकिन बीजेपी अब क्षेत्रीय दलों के किले में तेजी से सेंध लगा रही है। इसीलिए क्षेत्रीय दल दिल्ली में बीजेपी से सीधा टकराव नहीं चाहते हैं और वे दिल्ली और अपने राज्य की राजनीति को अलग–अलग रखना चाहते हैं। इसका सबसे सफल मॉडल ओडिशा रहा है जहां एक ही दिन हुए चुनाव में दिल्ली के लिए लोगों ने मोदी को वोट दिया तो विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक को। बीजेडी लगातार संसद में बीजेपी को मदद करती रही है।